प्रेस विज्ञप्ति

इंडिया अर्बन कॉन्फ्रेन्स 2011 : 'साक्ष्य और अनुभव'
भारत की शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए सार्थक पहल के मकसद से विभिन्न पक्षों के साथ संवाद शुरू

दिल्ली, भारत, 09 नवंबर, 2011 : आईआईएचएस, जनाग्रह और साउथ एशियन स्टडीज़ काउंसिल, येल ने आज यहां भारत में पहली बार 'इंडिया अर्बन कॉन्फ्रेंस (आईयूसी 2011) : साक्ष्य एवं अनुभव' श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की।

सम्मेलन का शुभारंभ **'एजुकेशन, इनोवेशन एंड इंडियाज़ अर्बन ट्रांसफॉरमेशन'** विषय पर आधारित पैनल चर्चा के साथ हुआ जिसमें बुद्धिजीवियों के अलावा शैक्षिक जगत की हस्तियों और प्रमुख नीति–निर्माताओं ने शहरी परिप्रेक्ष्य में अंतर्निहित राष्ट्रीय विकास के अवसरों का लाभ उठाने में शैक्षिक संस्थानों तथा अन्य केंद्रों की भूमिका की चर्चा की। इस पैनल चर्चा की अध्यक्षता **डॉ सुबीर गोकर्ण,** डिप्टी गवर्नर, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने की तथा इसमें भाग लेने वाली अन्य हस्तियों में सार्वजनिक सूचना, ढांचागत तंत्र तथा आविष्कारिता पर प्रधानमंत्री के सलाहकार **सैम पित्रोदा,** येल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर **रिचर्ड लेविन तथा** राष्ट्रीय समन्वयक सेवा–भारत **रेनाना झबवाला** शामिल थे।

इसके बाद, भारत में अब तक के सबसे बड़े शहरी सम्मेलन का आयोजन 17–20 नवंबर, 2011 को मैसूर स्थित इंफोसिस ट्रेनिंग सेंटर में किया जाएगा। मैसूर सम्मेलन का आयोजन पहली बार 600 से अधिक राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर के नीति–निर्माताओं, नीति–क्रियान्वयनकर्ताओं, शिक्षाविदों, छात्रों, नागरिक समाज के सदस्यों और उद्योग से जुड़े लोगों को शामिल किया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत के शहरी विकास की राह में पेश आने वाली चुनौतियों की पहचान और उनसे निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में संवाद प्रक्रिया को बेहतर बनाने और भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग–अलग फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे बहुपक्षीय और गहन संवाद मुमकिन हो सके। माननीय आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमारी शैलजा उद्घाटन भाषण देंगी जबकि कर्नाटक के माननीय कानून एवं शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार समापन भाषण देंगे। इस सम्मेलन के परिणामों को दिल्ली में आगामी 21 नवंबर, 2011 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाली पैनल चर्चा के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।

शहरी समस्याओं से निपटने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों की सार्वजनिक–निजी, सामुदायिक या निजी पहल का खाका तैयार करने वाली छात्रों की 170 से अधिक टीमों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता – संक्रांति का फाइनल राउंड भी मैसूर में आयोजित किया जाएगा। इसके आधार पर

तीन शीर्ष टीमें चुनी जाएंगी और प्रत्येक को तीन–तीन लाख रु का पुरस्कार तथा उनके विचारों को ठोस रूप देने के लिए आईआईएचएस की ओर से तकनीकी सहयोग दिया जाएगा।

इस श्रृंखला की परिणति विज्ञान भवन में 22 नवंबर, 2011 को आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय नीतिगत संवाद प्रक्रिया के रूप में होगी। दिल्ली संबंधी नीतिगत सम्मेलन शहरीकराण के बारे में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और संवाद को ताजा करने के साथ–साथ नए प्रश्नों को भी उठाएगी जिससे भारत की राष्ट्रीय विकास रणनीति, नीति निर्धारण और कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा शहरी संदर्भों में नई पहल को बढ़ावा मिल सकें। इस आयोजन से भारत के 150 अग्रणी नीति–निर्माताओं, विचारकों तथा पेशेवरों को जोड़ा जाएगा जो शहरीकराण की चुनौतियों तथा विकास के दायित्वों के संदर्भ में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर विचार–विमर्श करेंगे।

आईयूसी दिल्ली नीतिगत सम्मेलन को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, माननीय शहरी विकास मंत्री कमल नाथ और माननीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमारी शैलजा संबोधित करेंगे। डॉ राकेश मोहन, उपाध्यक्ष, आईआईएचएस; रेनाना झबवाला, राष्ट्रीय समन्वयक, सेवा–भारत; डॉ इशर आहलूवालिया, अध्यक्ष, शहरी ढांचागत तंत्र एवं सेवा संबंधी उच्च स्तरीय समिति; श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग पैनल चर्चा में भाग लेंगे।

सम्मेलनों की इस श्रृंखला के माध्यम से सर्वसमाहित और टिकाऊ शहरीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में आवश्यक प्रमुख कार्य/पहल की पहचान की जाएगी। यह आयोजन शोधकर्ताओं, नीति–निर्माताओं, पेशेवरों और नागरिकों के बीच ऐसी परामर्श प्रक्रिया की शुरूआत करेगा जो इन चुनौतियों के संदर्भ में शोध एवं कार्य योजना को प्रारंभ करेगी। साथ ही, यह नीति, व्यवहार तथा नागरिक समाज के स्तर पर पहल के बारे में सूचना देने के लिए बहुत–स्तरीय संवाद हेतु मुक्त 'मंच' का भी सृजन करेगा।

आईयूसी 2011 के लिए शहरों तथा नवीन पहल करने वाले स्थलों से साक्ष्य और अनुभवों को लिया जाएगा, और 'भूमि, आवास तथा ढांचागत तंत्र', 'शहरी जल', 'शहरी शिक्षा', 'शहरी स्वास्थ्य', 'सार्वजनिक संस्कृति में शहर', 'शहरी शासन एवं नागरिकता', 'वित्तीय सर्वसमाहित एवं शहरी अर्थव्यवस्था' और 'शहरी नियोजन' जैसे आठ प्रमुख विषयों पर विचार–विमर्श किया जाएगा। इन विषयों को अलग–अलग कन्टेंट भागीदारों द्वारा दिशा–निर्देशन दिया जाएगा, जो कि किसी प्रमुख शोध समूह या नागरिक समाज से जुड़े संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, ये हैं – अर्घ्यम, बेंगलुरु; द्रोणा (डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर नेचर आर्ट एंड हेरिटेज), गुड़गांव; आईएफएमआर फाइनेंस फाउंडेशन, चेन्नई; पीएचएफआई (पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया), दिल्ली; इंडिया अर्बन स्पेस फाउंडेशन (आईयूएसएफ), बेंगलुरु; और प्रथम, मुंबई एवं दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैन सैटलमेंट्स (आईआईएचएस) तथा जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीज़नशिप एंड डेमोक्रेसी

(जेसीसीडी) भी क्रमशः 'लैंड, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर' तथा 'अर्बन गवर्नेंस एंड सिटीज़नशिप' विषयों पर आधारित संत्रों का संचालन करेंगे।

इस सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन शहरी विकास एवं आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रियों के साथ सहयोग के आधार पर किया जा रहा है। आईडीएफसी और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय दिल्ली नीतिगत सम्मेलन के प्रमुख प्रायोजक हैं जबकि हडको इस सम्मेलन से अतिरिक्त प्रायोजक के तौर पर संबद्ध है। इंफोसिस ने इसके लिए मैसूर स्थित अपनी प्रशिक्षण इकाई तथा रिहाइशी कक्षों के इस्तेमाल को उपलब्ध कराया है। संक्रांति कॉलेज स्टूडेंट चैलेन्ज को रॉकफैलर फाउंडेशन, मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन तथा पिरोजशा गोदरेज फाउंडेशन से सहयोग हासिल है जबकि सिटी इन पब्लिक कल्चर थीम को एसपीए–भोपाल प्रायोजित कर रहे हैं।

आईयूसी फ्रेमवर्क के महत्व के बारे में श्री रमेश रमानाथन, सह–संस्थापक, जेसीसीडी ने कहा, ''शहरीकरण आज भारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ तक जा पहुंचा है। शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने ओर इसके अवसरों का लाभ उठाने के लिए व्यापक स्तर पर नीतिगत फेरबदल करने की जरूरत होगी जो केंद्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर ही की जा सकती है। इन नीतिगत बदलावों को आंकड़ों के परिप्रक्ष्य में किया जाना चाहिए जो शिक्षविदों तथा जमीनी स्तर पर कार्यरत पेशेवरों से लिए जाने चाहिए। इंडिया अर्बन कॉन्फ्रेंस ऐसा अनूठा मंच है जो इस प्रकार के आंकड़ों के संदर्भ में हमारे शहरी मसलों पर चर्चा के लिए विभिन्न पक्षों को एकजुट करेंगे। हमें आशा है कि आईयूसी देश में शहरी मसलों के संबंध में नवीन अनुसंधान, पूछताछ और दस्तावेजीकरण के नए दौर की शुरूआत करेगा।''

इस सम्मेलन के बारे में अरोमर रेवी, निदेशक, आईआईएचएस ने कहा, ''भारत के जनगणना आंकड़ों से, इतिहास में पहली बार देखने में आया है कि देश में शहरी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले अधिक बढ़ी है। इसके अलावा, अगले कुछ दशकों में भारत के शहरी इलाकों में जीडीपी मौजूदा 65 प्रतिशत से बढ़कर करीब 80 फीसदी तक पहुंच जाएगी, बशर्ते समुचित विनियमन एवं निवेश, शासन और संस्थागत हस्तक्षेप बने रहें। इन संरचनात्मक बदलावों और गरीबी तथा सर्वसमाहित विकास के बुनियादी सवालों से निपटने के लिए शहरी तथा ग्रामीण भारत के बारे में नए सिरे से सोच–विचार करने तथा उनके बीच मजबूत संपर्क–सेतु कायम करने की जरूरत है। आईयूसी भारत के भविष्य में विकास को प्रभावित करने वाले नीतिगत तथा शोध संबंधी सवालों के परिप्रेक्ष्य में विचार–विमर्श करता है। यह अलग–अलग क्षेत्रों तथा संस्थागत समूहों के बीच तीन स्तरों (केंद्र, राज्य एवं शहरों) के बीच खुले विचार–मंथन का मंच उपलब्ध कराता है।''

यह सम्मेलन श्रृंखला राष्ट्रीय नीतिगत एजेंडा से संबंधित दो अवसरों की पड़ताल करती है, पहला है निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक शर्त के तौर पर भारत का शहरी रूपांतरण, और

INDIA URBAN CONFERENCE
2011: EVIDENCE & EXPERIENCE

दूसरा प्रभावी, सर्वसमाहित तथा टिकाऊ ग्रामीण एवं शहरी विकास के संदर्भ में इस रूपांतरण में निहित संभावनाएं।

आयोजकों के बारे में

इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैन सैटलमेंट्स के बारे में

इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैन सैटलमेंट्स (**आईआईएचएस**) राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक संस्थान है जो भारतीय बस्तियों में बराबरी के, टिकाऊ और कुशल बदलाव लाने के लिए संकल्पबद्ध है। आईआईएचएस भारत की ऐसी पहली 'नेशनल यूनीवर्सटी फॉर इनोवेशन' है जिसका वित्तीय संचालन और प्रबंधन स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यह अपनी तरह का पहला, आविष्कारिता–उन्मुख ज्ञान आधारित संस्थान है जो पारंपरिक उत्कृष्टता, आयाम और समाहित करने जैसे मोर्चे पर अंतरों को पाटने का प्रयास करता है। आईएचएस के बारे में और जानकारी www.iihs.co.in पर उपलब्ध है।

जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीज़नशिप एंड डेमोक्रेसी

जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीज़नशिप एंड डेमोक्रेसी (जेसीसीडी) स्थापित गैर–मुनाफा प्राप्त संगठन है जो शहरी भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काम करता है। इस गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाले दो संकेतक हैं : नागरिकता की गुणवत्ता और ढांचागत तंत्र तथा सेवाओं का स्तर। जनाग्रह के कार्यक्षेत्र में केंद्र के साथ विचार–मंथन शामिल है जिसका मकसद शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना, जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाना और लोकतंत्र की जड़ों को सींचना है। जनाग्रह एप्लायड रिसर्च प्रोग्राम (जे–एआरपी), जो कि जेसीसीडी की ओर से इस सम्मेलन को समर्थन दे रहा है, ऐसा बुनियादी कार्यक्रम है जिसका मकसद शिक्षा बिरादरी के सहयोग से, आंतरिक खपत (जमीनी स्तर तथा एडवोकेसी संबंधी प्रयासों के लिए) और बाहरी प्रकाशन के लिए प्राइमरी डाटा/साक्ष्य तैयार करना है। जेसीसीडी के बारे में अधिक जानकारी www.janaagraha.org पर उपलब्ध है।

येल यूनीवर्सटी, साउथ एशियन स्टडीज़ काउंसिल

येल यूनीवर्सटी स्थित साउथ एशियन स्टडीज़ काउंसिल दक्षिण एशिया के बारे में, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका शाामिल हैं, ऐतिहासिक और समकालीन समझ को व्यापक के लिए प्रतिबद्ध है। येल यूनीवर्सटी में मैकमिलन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज़ के तहत्, काउंसिल पारंपरिक दक्षिण एशिया तथा क्षेत्र के आधुनिक स्वरूप को एकीकृत कर, शिक्षण एवं शोध का मेल कराते हुए विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में बौद्धिक आदान–प्रदान की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में संलिप्त है। साउथ एशियन स्टडीज़ काउंसिल के बारे में अधिक जानकारी www.yale.edu/macmillan/southasia पर उपलब्ध है।

कॉन्टैक्स्ट एंकर्स के बारे में

INDIA URBAN CONFERENCE
2011: EVIDENCE & EXPERIENCE

अर्घ्यम (बेंगलुरु) : अर्घ्यम सार्वजनिक चैरिटेबल फाउंडेशन है जो जल एवं स्वच्छता से जुड़े मसलों पर कार्यरत है। संगठन इन दोनों से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में शोध, क्रियान्वयन और एडवोकेसी से संबंद्ध है।

द्रोणा (डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर नेचर आर्ट एंड हेरिटेज), गुड़गांव – हरियाणा : द्रोणा ऐतिहासिक महत्व के शोध कार्यों, दस्तावेजीकरण और प्राचीन स्मारकों का समुदाय की मदद से कायाकल्प करने से संबद्ध है। यह संगठन सांस्कृतिक संस्कृतियों जैसे स्थानीय कलाओं के संवर्धन के अलावा स्वदेश में ही निर्मित सामग्री एवं तकनीकों आदि को बढ़ावा देने तथा समाज को प्रकृति एवं विरासत को सहेजने के बारे में बताती है।

आईएफएमआर फाइनेंस फाउंडेशन (चेन्नई) : आईएफएमआर ट्रस्ट निजी क्षेत्र के तहत् कार्यरत है जिसका मकसद प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक उपक्रम की संपूर्ण पहुंच वित्तीय सेवाओं तक सुनिश्चित करना है। विभिन्न भागीदारों के साथ काम करते हुए यह सर्वसमाहित वित्तीय प्रणाली विकसित करने के लिए व्यवस्थागत बदलाव लाने पर जोर देती है।

इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैन सैटलमेंट्स (आईआईएचएस) : इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैन सैटलमेंट्स (**आईआईएचएस**) राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक संस्थान है जो भारतीय बस्तियों में बराबरी के, टिकाऊ और कुशल बदलाव लाने के लिए संकल्पबद्ध है। आईआईएचएस भारत की ऐसी पहली 'नेशनल यूनीवर्सटी फॉर इनोवेशन' है जिसका वित्तीय संचालन और प्रबंधन स्वतंत्र रूप से किया जाता है और यह शहरी एवं विकासात्मक रूपांतरण प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है।

इंडिया अर्बन स्पेस फाउंडेशन (आईयूएसएफ) : पंजीकृत, गैर–मुनाफा प्राप्त ट्रस्ट है जिसे शहरी भारत में उन सुधारों को लाने के लिए मकसद से स्थापित किया गया जो आधुनिक शहरी भारत की मांगों को संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरे में पूरा कर सकें। फाउंडेशन भूमि अधिकारों को स्थापित करने, विकास संबंधी योजनाएं तैयार करने के साथ–साथ शहरी–ग्रामीण एकीकरण पर जोर देता है।

जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीज़नशिप एंड डेमोक्रेसी : जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीज़नशिप एंड डेमोक्रेसी (जेसीसीडी) स्थापित गैर–मुनाफा प्राप्त संगठन है जो शहरी भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काम करता है। इस गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाले दो संकेतक हैं : नागरिकता की गुणवत्ता और ढांचागत तंत्र तथा सेवाओं का स्तर।

प्रथम : प्रथम भारत में उपेक्षित समुदाय के बच्चों को स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने के लिए कार्यरत गैर–सरकारी संगठन है। यह ग्रामीण और शहरी इलाकों में काम करता है।

पीएचएफआई (पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया – दिल्ली) : पीएचएफआई सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शोध और नीतिगत विकास कार्यों में स्वतंत्र रूप से कार्यरत फाउंडेशन है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यापक आयामों पर ध्यान जमाती है जिसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली, रोगों से बचाव में कारगर तथा उपचारी सेवाएं शामिल हैं।

द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटैक्चर (एसपीए–दिल्ली) : विशिष्ट मानद विश्वविद्यालय है जो मानव पर्यावास और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिलाता है। यह शहरी नियोजन तथा विकास में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराता है। इसका कैम्पस दिल्ली में है। स्कूल ने आर्किटैक्चर, शहरी डिजाइन, पर्यावरण अध्ययन, संरक्षण अध्ययन, आवासीय अध्ययन, ग्रामीण विकास, परिवहन अध्ययन, शहरी अध्ययन और इनोवेटिव स्पेटियल प्लानिंग पर उच्च स्तरीय अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवांस्ड स्टडीज़ की स्थापना की है। इसके अलावा, कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर आधारित सुविधाओं के लिए सेंटर फॉर एनेलिसिस एंड सिस्टम्स स्टडीज़ भी कार्यरत है।

मीडिया संपर्क :

गुटनबर्ग कम्युनिकेशंस	**आईयूसी संपर्क, जनाग्रह**	**आईयूसी संपर्क, आईआईएचएस**
सुखमणी बिक्रम	उना वी गोविंदराजन	राघवेन्द्र राजू
sukhmani@gutenbergpr.com	unna@janaagraha.org	rraju@iihs.ac.in
+91-9871012654		+91 9740220875